न्यायमूर्ति **एम. आर. अग्निहोत्री** *के समक्ष*

चंद कृष्ण मेहता और एक अन्य, **याचिकाकर्ता**

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1988 **का** 5246।

26 मई, 1989।

विस्थापित व्यक्ति *(*मुआवजा और पुनर्वास*)* अधिनियम, 1954 **- धारा** 20 - **पैकेज डील के माध्यम से हस्तांतरित की गई विस्थापित संपत्ति** - असंतुष्ट दावेदार - संयुक्त सचिव (पुनर्वास) के अनुमोदन का अधिकार - यदि आवश्यक हो।

यह अधिनिर्णित किया गिया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की तरह असंतुष्ट दावेदारों के अधिकारों का सम्मान किया जाना है और उनके द्वारा प्रार्थना की गई और तहसीलदार (बिक्री) -सह-प्रबंध अधिकारी द्वारा अनुशंसित उप-शहरी भूमि का आवंटन करके उन्हें मुआवजा देकर दावों को संतुष्ट किया जाना है। कानून का यह सुसंगत दृष्टिकोण होने के नाते, तहसीलदार (बिक्री) सह प्रबंध अधिकारी डॉ. तरलोक सिंह द्वारा भूमि पुनर्स्थापन मैनुअल के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 20 के तहत याचिकाकर्ताओं को उनके असंतुष्ट दावों की संतुष्टि में आवंटन देने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। प्रबंध अधिकारी द्वारा संयुक्त सचिव (पुनर्वास) जैसे किसी भी उच्च प्राधिकारी से कोई अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी और ऐसा कोई भी संदर्भ केवल एक अधिशेष और निरर्थक था जिसका तहसीलदार (बिक्री) सह-प्रबंध अधिकारी की क्षमता और अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(पैरा 9 और 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद *226/227* के तहत रिट याचिका **में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय इस मामले के रिकॉर्ड को मंगाने की कृपा करे और अवलोकन के बाद आगे की कृपा करे:** –

(1) **तहसीलदार *(*बिक्री*)* द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि को आवंटित करने से इनकार करने के लिए प्रतिवादियों की आक्षेपित कार्रवाई/आदेश को रद्द करते हुए प्रमाण** पत्र **की प्रकृति में रिट जारी करना।** याचिकाकर्ताओं के लिए 4-अनुलग्नक **पी *5*** के तहत।

(2) **परमादेश की** प्रकृति में एक रिट **जारी करें जिसमें प्रतिवादियों को पट्टी इंसार में स्थित उपनगरीय कृषि भूमि का अर्ध-स्थायी आवंटन जारी करने का निर्देश दिया जाए। पानीपत, जिला कमल द्वारा तहसीलदार *(*बिक्री*)* -सह-प्रबंध अधिकारी/प्रतिवादी संख्या *10* द्वारा प्रस्तावित।** 4 **और कानून के अनुसार उसके संबंध में मालिकाना अधिकार प्रदान करना**;

(3) **कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।**

(4) **याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या *10* के रूप में सभी प्रतिवादियों पर अग्रिम नोटिस की सेवा से छूट दी गई है।** 4 **सरकार याचिकाकर्ताओं को नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के निपटान के लिए कदम उठा रही है।**

(5) **याचिकाकर्ताओं को अनुलग्नक पी *-1*** से **पी *-6*** की प्रमाणित प्रतियां **दाखिल करने से छूट**;

(6) **याचिकाकर्ताओं को इस याचिका की लागत का भुगतान करें।**

यह भी प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, विचाराधीन भूमि का किसी भी तरह से निपटान किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सोमनाथ सैनी के साथ अधिवक्ता पीसी मेहता।

एस. के. जैन, अधिवक्ता, प्रतिवादी **संख्या *10* के लिए।** -2 **से** 5.

आदेश

एम. आर. अग्निहोत्री, जे.

(1) भारत सरकार के अनुच्छेद 226 और सी 227 एच के तहत दायर इस याचिका में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए शामिल संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या असंतुष्ट दावेदारों के अधिकार, जिनके दावों को विधिवत सत्यापित किया गया था और विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के तहत उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया पहले ही उप-शहरी कृषि भूमि के आवंटन से शुरू हो गई थी, "पैकेज डील" के तहत विस्थापित भूमि के हस्तांतरण के साथ स्वचालित रूप से बह गया है या अधिनियम के तहत प्राधिकरण) अभी भी कानून में असंतुष्ट दावेदारों को आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए सक्षम हैं ताकि उनके द्वारा की गई भूमि की पसंद को ध्यान में रखते हुए उप-शहरी कृषि भूमि के आवंटन के लिए उनके आवेदन स्वीकार करके उन्हें मुआवजा दिया जा सके। जवाब असंतुष्ट दावेदारों के पक्ष में है क्योंकि मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सैद्धांतिक रूप से तय किया जा चुका है और इस संबंध में कई मामलों में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।

(2) (संक्षेप में, श्री सिरी राम मेहता जो पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति थे, के पास कुछ ग्रामीण कृषि भूमि थी।

1947 में देश के विभाजन से पहले लायलपुर और मोंटगोमरी जिले। पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई भूमि के बदले में, श्री मेहता को पट्टी इंसार और पट्टी राजपूतान, तहसील पानीपत, जिला कमल में 55 मानक एकड़ की सीमा तक कृषि भूमि आवंटित की गई थी, इसके अलावा 12 'मानक एकड़ के क्षेत्र और पश्चिमी पाकिस्तान में उनके द्वारा छोड़े गए बगीचे के बदले 13 जे इकाइयों को बगीचे के रूप में आवंटित किया गया था। बाद में, जब यह पता चला कि श्री मेहता को आवंटित भूमि उस क्षेत्र से कम थी जिसके वे वास्तव में हकदार थे, तो श्री मेहता ने अपने आवेदन में उनके द्वारा दर्शाए गए भूमि के शेष क्षेत्र को आवंटित करके कमी को पूरा करने के लिए एक आवेदन किया। श्री मेहता के बार-बार अनुरोध का कोई नतीजा नहीं निकला और इस बीच 1975 में उनका निधन हो गया। इसके बाद, उनके बेटे चांद कृष्ण मेहता, याचिकाकर्ता नंबर 1, और बेटी श्रीमती कुशाम लता बाटला, याचिकाकर्ता नंबर 2, ने अपने पिता को किए गए आवंटन में कमी को पूरा करने के लिए पुनर्वास अधिकारियों से संपर्क किया। वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई और उनके द्वारा किए गए दावे को सत्यापित करने के बाद, सहायक रजिस्ट्रार-सह-प्रबंध अधिकारी, पुनर्वास विभाग, हरियाणा ने 8 अगस्त, 1984 को निम्नलिखित आशय का निर्देश जारी किया: –

> पीठ ने कहा, 'मैं यह कहना चाहता हूं कि आवेदकों के पिता को भूमि आवंटन में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए. श्री राजिन्दर कृष्ण द्वारा तैयार किए गए खाते के अनुसार, श्री सिरी राम 7-13 जे S.As भूमि के अतिरिक्त आवंटन के हकदार हैं। मैं, एक प्रबंध अधिकारी के रूप में, इसकी अनुमति देता हूं और यह आवंटन उन्हें क्षेत्र और ग्रेड की उपलब्धता के अनुसार जिला कमल में किया जाना चाहिए। तदनुसार जारी करने का आदेश दें।

(3) उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने तहसीलदार (बिक्री), कमल से इसके कार्यान्वयन के लिए संपर्क किया और पट्टी इंसार, पानीपत, जिला कमल के राजस्व एस्टेट में स्थित उप-शहरी कृषि भूमि की अपनी पसंद को दर्शाया। चूंकि याचिकाकर्ताओं के दिवंगत पिता उस पट्टी के एक मौजूदा आवंटी थे और इस प्रकार उप-शहरी क्षेत्र के आवंटन के लिए अधिमान्य अधिकार था और क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पिता को पहले से आवंटित क्षेत्र उनके दावे की संतुष्टि में उनके द्वारा आवंटित किए जाने के लिए अनुरोध किए गए क्षेत्र से सटा हुआ था, तहसीलदार (बिक्री) -सह-प्रबंध अधिकारी, प्रतिवादी संख्या 4, अनुरोध को कानून के अनुसार पाया गया और इसे मंजूरी देने के बाद संयुक्त सचिव (पुनर्वास), प्रतिवादी संख्या 3 को आवश्यक कागजात भेज दिए गए। हालांकि संयुक्त सचिव (पुनर्वास) का यह संदर्भ वैधानिक नहीं था या

प्रक्रियात्मक आवश्यकता, चूंकि प्रबंध अधिकारी स्वयं डॉ त्रिलोक सिंह द्वारा भूमि पुनर्स्थापन मैनुअल के प्रावधानों के साथ उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत विस्थापित व्यक्तियों को उनके असंतुष्ट दावों की संतुष्टि में आवश्यक आवंटन करने के लिए सक्षम था, फिर भी प्रशासनिक पक्ष में तहसीलदार (बिक्री) -सह-प्रबंध अधिकारी द्वारा संयुक्त सचिव (पुनर्वास) का अनुमोदन प्राप्त करना उचित और उचित समझा गया था। उनके द्वारा संयुक्त सचिव (पुनर्वास) के अंतिम अनुमोदन के अधीन थे। हालांकि, तहसीलदार (बिक्री) - सह-प्रबंध अधिकारी, याचिकाकर्ताओं द्वारा बार-बार अभ्यावेदन और अनुरोध किए जाने के बावजूद काफी समय तक अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। अंततः, 26 अक्टूबर, 1987 को सहायक रजिस्ट्रार, पुनर्वास विभाग, हरियाणा द्वारा तहसीलदार (बिक्री), कमल को पत्र (अनुबंध पृष्ठ 5) भेजा गया, जिसमें सूचित किया गया कि सरकार ने गांव पट्टी इंसार (पानीपत) में उपनगरीय आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि, यह जोड़ा गया कि "आवंटी को नियमों और

निर्देशों के अनुसार कुछ अन्य गांवों में भूमि आवंटित की जा सकती है"। याचिकाकर्ताओं को गांव पट्टी इंसार (पानीपत) में भूमि के आवंटन के अनुमोदन के मामले में सरकार के इस इनकार से व्यथित होकर, दिनांक 26 अक्टूबर, 1987 (अनुलग्नक पृष्ठ 5) के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर इसे रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि यह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और **परमादेश** की रिट जारी करने के लिए भी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके असंतुष्ट दावे की कमी को पूरा करके क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक आवंटन करें।

(4)16 जून, 1988 को रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, मोशन बेंच द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं को आवंटित की जाने वाली संपत्ति के निपटान पर रोक रहेगी और मुख्य याचिका को एक वर्ष के भीतर सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया गया था।

(5) जब मामला आज सुनवाई के लिए आया, तो प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से पेश हुए वकील श्री एसके जैन ने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि वह लिखित बयान दायर कर सकें जो पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान दायर नहीं किया गया था। इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इतने लंबे समय तक इसे दायर नहीं करने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था।

(6) हालांकि, बहस के दौरान, विद्वान राज्य के वकील ने तर्क दिया कि संयुक्त सचिव (पुनर्वास), प्रतिवादी नंबर 3, 1961 में 'पैकेज डील' द्वारा विस्थापित संपत्ति के हस्तांतरण के बाद इसका निपटान करने के लिए सक्षम थे, और इस तरह, वह

याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भूमि के आवंटन के लिए तहसीलदार (बिक्री) सह-प्रबंध अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश को अस्वीकार करने के लिए सक्षम था। वकील ने आगे तर्क दिया कि यह मानते हुए कि याचिकाकर्ताओं का मामला डॉ. तिरलोक सिंह के भूमि पुनर्वास मैनुअल में निहित प्रावधानों द्वारा कवर किया गया था, उक्त मैनुअल को 1961 के बाद आवंटन करने के उद्देश्य से भरोसा नहीं किया जा सकता था जब केंद्र सरकार द्वारा 'पैकेज डील' द्वारा विस्थापित भूमि का हस्तांतरण किया गया था। परिणामस्वरूप, विद्वान राज्य वकील के अनुसार, उक्त भूमि पुनर्वास मैनुअल के अनुसार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आवंटन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था, न ही राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए क्षेत्र की पसंद के अनुसार भूमि का आवंटन करने के लिए कानून में बाध्य थी।

(7) उन्होंने अपने पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनीं। उनके द्वारा उद्धृत दृष्टांतों की जांच करने के बाद, मेरा विचार है कि प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया रुख केवल अति-तकनीकी है और कानून में टिकाऊ नहीं है और रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। मूल रूप से, देश के विभाजन के तुरंत बाद, जब विस्थापित व्यक्तियों को कृषि/उप-शहरी भूमि के आवंटन का प्रश्न उठा, तो केन्द्र/राज्य सरकारों के अनुभवी अधिकारियों द्वारा गहन विचार-विमर्श के बाद एक व्यापक और विस्तृत पद्धति विकसित की गई थी। उसी का परिणाम था कि डॉ. तिरलोक सिंह द्वारा भूमि पुनर्स्थापन नियमावली तैयार की गई। निस्संदेह, पुनर्वास प्राधिकारियों द्वारा 1961 तक उक्त मैनुअल अधिकार के अनुसार आवंटन किए गए थे, जब विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के तहत 'पैकेज डील' के माध्यम से विस्थापित संपत्ति को हस्तांतरित किया गया था। इसके बाद भी, आबंटन की प्रणाली पहले की तरह जारी रही और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1962 के अपने नीतिगत अनुदेशों के माध्यम से इसे सुदृढ़ किया गया (अनुपत्र पृष्ठ 6)। इन नीतिगत अनुदेशों के अनुसार, असंतुष्ट दावेदारों को भूमि का आबंटन निम्नलिखित शिष्टाचार ों में सख्ती से किया जाना था -

> ".....गांवों की ग्रेडिंग की योजना और इस विषय पर अन्य नियमों के अधीन असंतुष्ट दावेदारों को उनकी पसंद के अनुसार आवंटन किया जाना चाहिए। आंशिक रूप से असंतुष्ट दावेदारों को उनके मूल आवंटन के गांवों में आवंटन दिया जाना चाहिए और यदि कोई ग्रीया उपलब्ध नहीं है, तो पड़ोसी गांवों में,

2. किसी विशेष गांव में जमीन कब्जेदारों को निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने से पहले, सभी असंतुष्ट दावेदार जिन्होंने गांव में आवंटन के लिए आवेदन किया है या जिन्हें नियमानुसार गांव में आवंटन दिया जाना है, उन्हें पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए। **खसरा नंबरों की राहत का पालन करने के सामान्य नियम का** पालन किया जाना चाहिए और कोई भी कब्जाधारक जिसकी भूमि आवंटन उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, उसे खरीदने में सक्षम नहीं होना चाहिए।

3. इन अनुदेशों का पालन करने से यह देखा जाएगा कि अधिशेष भूमि का उपयोग निम्नलिखित क्रम या प्राथमिकता में किया जाना है:-

(1) असंतुष्ट दावेदारों को भूमि का आवंटन;

(2) पात्र निवासियों को निश्चित मूल्य पर बिक्री द्वारा; और

(3) सार्वजनिक नीलामी द्वारा।

इस प्रकार, असंतुष्ट दावेदारों को आवंटन को 1962 में भी राज्य सरकार द्वारा पहली प्राथमिकता के रूप में माना जाता रहा था और यह इस राजनीति के निर्णय के अनुसार है कि आवंटन उत्तरदाताओं द्वारा किया जाना है। इस नीतिगत निर्णय को 20 तारीख को कार्यकारी निर्देशों के रूप में संबंधित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया। अगस्त, 1962, अनुलग्नक पी6 को अब तक प्रतिस्थापित, वापस नहीं लिया गया है या संशोधित नहीं किया गया है। बहस के दौरान, प्रतिवादियों के विद्वान वकील से विशेष रूप से यह पूछा गया कि क्या निर्णय को रद्द कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है या नहीं, लेकिन बाद में कोई नीतिगत निर्णय नहीं दिखाया गया जिसके द्वारा उपरोक्त निर्णय को विशेष रूप से दरकिनार कर दिया गया था। यह स्थिति होने के नाते, प्रतिवादी अधिकारी 1954 अधिनियम के तहत 'पैकेज डील' के माध्यम से विस्थापित भूमि के हस्तांतरण के बाद भी याचिकाकर्ताओं को उनके पूर्वोक्त नीतिगत निर्णय के अनुसार भूमि का आवंटन करने के लिए बाध्य हैं।

(8) असंतुष्ट दावेदारों के अधिकारों की तुलना में 'पैकेज डील' के प्रभाव पर इस न्यायालय के दो खंडपीठ के फैसलों में पहले ही विचार किया जा चुका है, जिसमें बिशन सिंह और अन्य बनाम मुख्य निपटान आयुक्त और अन्य, ***(1),*** **और ग्राम** सभा और ग्राम पंचायत डाबा **बनाम मुख्य निपटान आयुक्त और अन्य,** (2) संक्षेप में, इन दोनों निर्णयों में, हरबंस सिंह, मुख्य न्यायाधीश। और बी. आर. तुली, जे. ने कहा कि

(1) 1973 पी.एल.जे.
(2) 1973 पी.एल.जे., 398.

पुनर्वास अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के पास 'पैकेज डील' के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित संपत्ति से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

"अधिशेष संपत्ति जो 'पैकेज डील' की विषय-वस्तु है, वह राज्य सरकार की है, लेकिन यह असंतुष्ट दावेदारों की संतुष्टि के लिए एक शुल्क से प्रभावित है। जहां तक असंतुष्ट दावेदारों को मुआवजे के भुगतान का संबंध है, पैकेज डील के तहत राज्य सरकार को मुआवजा पूल में अधिशेष संपत्ति के हस्तांतरण के बावजूद, पुनर्वास अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के पास शक्तियां बनी हुई हैं, जैसा कि उनके पास पैकेज डील से पहले था।..... एक तरह से, इसलिए, असंतुष्ट

दावेदारों को नियमों के अनुसार अपने दावों की संतुष्टि के लिए पूरे मुआवजा पूल पर एक प्रकार का शुल्क मिला है।

(9) इस प्रश्न के संबंध में कि क्या डॉ. तिरलोक सिंह द्वारा भूमि पुनर्स्थापन मैनुअल पर भरोसा किया जा सकता है, प्रतिवादियों की यह दलील कि 1961 के 'पैकेज डील' के बाद यह अप्रासंगिक हो गई है और इसका कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है, खारिज कर दिया गया है और इसका कोई आधार नहीं है। यह इस न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों से स्पष्ट होगा जिसमें डा त्रिलोक सिंह की भूमि पुनर्स्थापन नियमावली का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कुछ का उल्लेख करने के लिए, **सुचा में: सिंह और अन्य** वी। **गुरदयाल सिंह और अन्य,** (3) (डीबी) श्री न्यायमूर्ति, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, इस न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि उस समय उनके लॉर्डशिप ने प्रबंध अधिकारी, अधिकारी और सहायक निपटान आयुक्त की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए कहा था कि,

> "ग्रेड II और ग्रेड III भूमि के हकदार व्यक्तियों को ग्रेड I भूमि के आवंटन के खिलाफ कोई निषेध नहीं है, लेकिन श्री तरलोक सिंह द्वारा तैयार भूमि पुनर्वास मैनुअल इंगित करता है कि ग्रेड I भूमि के मालिकों को ग्रेड I भूमि के आवंटन में वरीयता मिलनी चाहिए। भूमि पुनर्स्थापन नियमावली के अध्याय IV के पृष्ठ 89 पर पैरा 18 इस प्रकार है -

ओम प्रकाश और अन्य में **भारत संघ और अन्य,** (4), प्रयोजनों के लिए भूमि की प्रकृति, सीमा या गुणवत्ता पर विचार करते समय।

(3) 1977 पीएलजे 6.
(4) एआईआर 1971 एससी 771,

आबंटन के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की -

> "विद्वान अधिवक्ता ने हमें तरलोक सिंह द्वारा भूमि पुनर्वास मैनुअल के पृष्ठ 49 का संदर्भ दिया है, जिसे एक मानक कार्य कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि भूमि के वर्ग के लिए जमाबंदी में प्रवेश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

इसलिए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की तरह असंतुष्ट दावेदारों के अधिकारों का अभी भी सम्मान किया जाना है और तहसीलदार (बिक्री) -सह-प्रबंध अधिकारी द्वारा अनुशंसित उप-शहरी भूमि का आवंटन करके, उन्हें मुआवजा देकर दावों को संतुष्ट किया जाना है।

(10) कानून का सुसंगत दृष्टिकोण होने के कारण, तहसीलदार (बिक्री) -सह-प्रबंध अधिकारी डॉ. तरलोक सिंह द्वारा भूमि पुनर्स्थापन मैनुअल के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 20 के तहत याचिकाकर्ताओं को उनके असंतुष्ट दावों की संतुष्टि में आवंटन देने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। प्रबंध अधिकारी द्वारा संयुक्त सचिव (पुनर्वास) जैसे किसी भी उच्च प्राधिकारी से कोई अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी और ऐसा कोई भी संदर्भ केवल अधिशेष और निरर्थक था जिसका तहसीलदार (बिक्री) सह-प्रबंध अधिकारी की क्षमता और अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तथ्य यह है कि भूमि का चयन और दावेदारों द्वारा पहले से ही रखे गए क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के चयन को अधिकारियों द्वारा आवंटन करते समय स्वीकार किया जाना चाहिए, L.Rs द्वारा साधु सिंह (मृत) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निम्नलिखित निर्देश से स्पष्ट होगा । बनाम **भारत संघ और अन्य,** (5), –

> "प्रतिवादी जिस क्षेत्र का हकदार पाया जा सकता है, उसका आवंटन जहां तक संभव हो, उसके पास पहले से मौजूद क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में किया जाएगा।

(11)प्रतिवादियों के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, यह देखा जाएगा कि एक तर्क यह भी दिया गया था कि इस न्यायालय को अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा प्रयोग की गई शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ***L.Rs*** **द्वारा** पाला सिंह (मृतक***)*** **के मामले में माना है**। बनाम **भारत संघ और अन्य,** (6)। संबंध में, यह गलती से एक विस्थापित व्यक्ति को पात्रता से अधिक भूमि के आवंटन का मामला था। यह उस संदर्भ में था कि

(5) एआईआर 1979 एससी 1609।
(6) एआईआर 1988 एससी 873।

त्रिलोचन सिंह **बनाम** महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक
एक और (ए एल बहरी, जे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि विस्थापित व्यक्ति को आवंटित अतिरिक्त भूमि 'पैकेज डील' संपत्ति थी, इसलिए इसे बेचा नहीं जा सकता था और न ही इसे प्रबंध अधिकारी द्वारा व्यक्ति को बेचने की अनुमति दी जा सकती थी और मुख्य निपटान आयुक्त विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम की धारा 24 के तहत सक्षम थे। 1954 में, क्षेत्र से अधिक भूमि के आवंटन को रद्द करने के लिए व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने का हकदार था। फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि तहसीलदार (बिक्री) सह प्रबंध अधिकारी असंतुष्ट दावेदारों को उनके आवंटन में कमी को पूरा करने के लिए भूमि का आवंटन करने के लिए सक्षम नहीं थे।

(12) नतीजतन, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और **प्रमाण पत्र** जारी करके, 26 अक्टूबर, 1987 (अनुबंध पी.5) के आक्षेपित आदेश को रद्द करता हूं, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि आवंटित करने से इनकार कर दिया है, और आगे **परमादेश** की रिट जारी करके प्रतिवादियों को पट्टी इंसार (पानीपत) में स्थित उप-शहरी कृषि भूमि का अर्ध-स्थायी आवंटन करने का निर्देश देता हूं। जिला कमल, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन किया गया है और तहसीलदार (बिक्री)-प्रबंध अधिकारी, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अनुशंसित है और उसके बाद इस फैसले की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं को इसके संबंध में मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता इस याचिका की लागत के भी हकदार होंगे जो 1,000 रुपये निर्धारित हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयो गनहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी
गुरुग्राम